नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 241
दि. 01.01.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

वेस्ट वॉटर नहीं बनेगा बोझ! भविष्य की 'प्यास' बुझाने के लिए सीएम योगी का मेगा प्लान तैयार

(जीएनएस)।

योगी सरकार ने साल 2030 तक 50 फीसदी और 2035 तक 100 फीसदी वेस्ट वॉटर का सुरक्षित पुनः उपयोग सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है. इससे कृषि से लेकर इंडस्ट्री तक में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा.

यूपी की योगी सरकार जल सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जा रही है. योगी सरकार ने साल 2030 तक 50 फीसदी और 2035 तक 100 फीसदी वेस्ट वॉटर का सुरक्षित पुनः उपयोग सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है. इससे कृषि से लेकर इंडस्ट्री तक में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके लिए व्यापक नीति, चरणबद्ध कार्ययोजना और मजबूत क्रियान्वयन तंत्र तैयार किया गया है. यह पहल न सिर्फ जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ जल प्रबंधन की मजबूत नींव भी रखेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत अब वेस्ट वॉटर को बोझ नहीं, बल्कि आर्थिक संसाधन के रूप में विकसित किया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही नीति के तहत उपचारित जल का उपयोग नगर निकायों के कार्यों, इंडस्ट्री, कृषि एवं गैर-पेय घरेलू उपयोग में किया जाएगा. इससे भूजल पर दबाव कम होगा और पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा.

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक जोगिन्दर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नदियों के संरक्षण को लेकर अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं. योगी सरकार ने वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है. इसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा.

पहला चरण (2025झ2030): जहां एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) और संग्रहण की सुविधा पहले से मौजूद है।

वहां 50 फीसदी वेस्ट वॉटर के पुनः उपयोग का लक्ष्य तय किया गया है.

दूसरा चरण (2030झ2035): इन क्षेत्रों में क्षमता विस्तार कर 100 फीसदी वेस्ट वॉटर के पुनः उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा.

तीसरा चरण (2045 तक): जहां अभी उपचार और संग्रहण की व्यवस्था नहीं है, वहां चरणबद्ध ढंग से 30 फीसदी, फिर 50 फीसदी और अंततः 100 फीसदी वेस्ट वॉटर के

अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुभकामनाएं दीं

(जीएनएस)।

अयोध्या में राम लला की प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश और विश्वभर के भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

श्री मोदी ने राम लला की प्राण-प्रतिष्ठा वर्षगांठ को भारत की आस्था और सांस्कृतिक विरासत का दिव्य उत्सव बताया। उन्होंने भारत और विदेश के असंख्य भक्तों की ओर से भगवान श्री राम के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन किया और सभी देशवासियों को अपनी असीम शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने सदियों पुराने संकल्प के ऐतिहासिक रूप से पूरा होने का स्मरण करते हुए कहा कि भगवान श्री राम की कृपा और आशीर्वाद से लाखों भक्तों की पांच शताब्दियों की पवित्र मनोकामना पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि राम लला फिर से अपने भव्य निवास में विराजमान हैं और यह वर्ष अयोध्या में धर्म ध्वज और राम लला की प्रतिष्ठा द्वादशी के गौरव का साक्षी है। प्रधानमंत्री ने पिछले माह इस धर्म ध्वज की पुण्य स्थापना का अवसर मिलने को अपना परम सौभाग्य बताया।

श्री मोदी ने कामना की कि मयार्दा पुरूषोत्तम प्रभु श्री राम की प्रेरणा से प्रत्येक नागरिक के हृदय में सेवा, समर्पण और करुणा की भावना गहरी हो। उन्होंने कहा कि ये मूल्य समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के सशक्त आधार हैं।

उच्च प्रदर्शन केंद्र के आधारशिला समारोह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन

(जीएनएस)।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएससी) में अत्याधुनिक उच्च प्रदर्शन केंद्र (एचपीसी) के शिलान्यास समारोह का आभासी माध्यम से उद्घाटन किया।

प्रस्तावित उच्च प्रदर्शन केन्द्र की कुल परियोजना लागत 75 करोड़ रुपये है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के 60 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सहयोग से विकसित किया जाएगा। यह एक ही स्थान पर एकीकृत, विश्व स्तरीय खेल विज्ञान और सहायक सुविधाएं प्रदान कर भारत में श्रेष्ठ एथलीट तैयार करने के परितंत्र में अहम योगदान देगा।

निर्माण पूरा होने पर, उच्च प्रदर्शन केन्द्र में खेल चिकित्सा, शक्ति और कंडीशनिंग, पुनर्वास और रिकवरी, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, मनोविज्ञान, पोषण, प्रदर्शन विश्लेषण और हाइड्रोथेरेपी की उन्नत सुविधाएं होंगी, जो एथलीटों की समग्र, वैज्ञानिक और डेटा-संचालित तैयारी सक्षम बनाएंगी।

आयोजन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि यह केंद्र, खेल स्पधाओं में भारत के केवल भाग लेने भर के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए पोडियम पर पदक हासिल करने वाले खेल राष्ट्र बनने के बदलाव को दशार्ता है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन" का मंत्र भारत के खेल तंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है।

खेल मंत्री ने कहा कि यह उच्च प्रदर्शन केंद्र सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण और स्वास्थ्य लाभ विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा निर्देशित हों, जिससे हमारे एथलीट उच्चतम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और उच्च परिणाम हासिल करने में सक्षम होंगे।

डॉ मांडविया ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कापोर्रेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योगदान की सराहना करते हुए इसे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान का बड़ा उदाहरण बताया।

राष्ट्रपति ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नव वर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है, "नए साल के शुभ अवसर पर, मैं देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं।" नव वर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। यह आत्मचिंतन और नए संकल्पों का भी अवसर है। इस अवसर पर, आइए हम राष्ट्र के विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें। "वर्ष 2026 हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाए और एक मजबूत तथा अधिक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा का संचार करे।"

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने सिस्टम इंजीनियरिंग फैसलिटी के उद्घाटन के साथ अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया

नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्टार्ट-अप तथा एमएसएमई के लिए समर्थन को बढ़ावा मिला

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) ने 31 दिसंबर 2025 को सिस्टम इंजीनियरिंग फैसिलिटी (एसईएफ) के उद्घाटन के साथ अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की सचिव एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेवानिवृत्त कमोडोर अमित रस्तोगी ने सात दशकों में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की यात्रा और गहन प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को सक्षम बनाने, स्टार्ट-अप और एमएसएमई का समर्थन करने तथा अनुसंधान परिणामों और बाजार में तैनाती के बीच की खाई को पाटने वाले मजबूत संस्थागत तंत्रों के निर्माण पर इसके नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की रणनीतिक पहलों, जिनमें विकसित भारत@2047, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत शामिल हैं, पर बल दिया और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के निर्माण के प्रति राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की प्रतिबद्धता को दोहराया।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के संबोधन के बाद, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन सिस्टम्स इंजीनियरिंग (आईएनसीओएसई) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान हुआ। यह समझौता ज्ञापन सहयोगात्मक नवाचार और क्षमता निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य सिस्टम इंजीनियरिंग प्रणालियों को सुदृढ़ करना है।

इस अवसर का एक प्रमुख आकर्षण सिस्टम इंजीनियरिंग फैसलिटी (एसईएफ) का उद्घाटन था, जो महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (पीसीसीओई) के साथ रणनीतिक सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय पहल है। सिस्टम इंजीनियरिंग फैसलिटी का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. एन. कलाइसेल्वी, महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सेवानिवृत्त) कमोडोर अमित रस्तोगी और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, आईएनसीओएसई के अध्यक्ष श्री प्रसन्ना राममूर्ति और पीसीसीओई के निदेशक डॉ. जीएन कुलकर्णी उपस्थित थे। अपने संबोधन में, डॉ. कलाइसेल्वी ने तकनीकी जटिलता के प्रबंधन, नवाचार को गति देने और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को स्केलेबल और तैनाती योग्य समाधानों में विकसित करने में सिस्टम इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

सिस्टम इंजीनियरिंग फैसिलिटी को एक राष्ट्रीय मंच के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य विचारों और प्रमाणित तकनीकी समाधानों के बीच की महत्वपूर्ण खाई को पाटकर इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स, एमएसएमई और नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाना है। संरचित सिस्टम इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं को संस्थागत रूप देकर, एसईएफ नवाचार जीवनचक्र में संपूर्ण सहायता प्रदान करता है, जिसमें आवश्यकताओं का विश्लेषण, सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन, मॉडलिंग और सिमुलेशन, एकीकरण, सत्यापन और प्रमाणीकरण शामिल हैं।

स्थापना दिवस समारोह में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान परिणामों में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करने के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के व्यापक जनादेश पर भी जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग समझौतों पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान हुए, जिनमें पश्चिम बंगाल के सीएसआईआर-सीएमईआरआई द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर प्रौद्योगिकी शामिल है, जिसका लाइसेंस मेसर्स मिस्त्रीजी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पटना को दिया गया। यह हस्ताक्षर सीएसआईआर के सीएमईआरआई के निदेशक डॉ. नरेश चंद्र मुर्मू की उपस्थिति में हुए।

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत ₹224 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि जारी

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की अनटाइड अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में ₹224.5762 करोड़ की राशि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी की है। यह अनुदान राज्य की 11279 पात्र ग्राम पंचायतों, 138 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 26 पात्र जिला पंचायतों के लिए है।

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त वर्ष के अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई

तमिलनाडु से जुड़े अधिकारियों ने मंत्रालय में हिंदी के प्रचार-प्रसार को नई गति दे दी, ये 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का उदाहरण: डॉ. जितेंद्र सिंह

हिंदी केवल भाषा नहीं राष्ट्रीय एकता की जीवंत अभिव्यक्ति डॉ. जितेंद्र सिंह

(जीएनएस)।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आज पृथ्वी भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री, पृथ्वी विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने की। बैठक में हिंदी के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान के व्यापक प्रसार, जनभागीदारी को सशक्त बनाने तथा राष्ट्रीय एकता के भाव को और सुदृढ़ करने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और समावेशी संवाद का माध्यम है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति की यह बैठक देश की बहुभाषिक आत्मा और राष्ट्रीय एकता की सशक्त झलक पेश करती है। केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के सचिव एवं सहायक सचिव को बधाई देते हुए कहा कि तमिलनाडु से जुड़े अधिकारियों के नेतृत्व में मंत्रालय में हिंदी के प्रचार-प्रसार को नई गति मिली है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर यह भी उल्लेख किया कि लगभग दो दशकों के बाद ऐसा सुखद संयोग बना है कि मंत्रालय में तमिलनाडु से जुड़े अधिकारियों के माध्यम से हिंदी कार्यों को संगठित रूप से आगे बढ़ाया जा सका है, जो 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को और मजबूत करता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वग्राही विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

34 जिलों की जिला पंचायतों के अध्यक्षों को 1 करोड़ रुपए का वार्षिक विवेकाधीन अनुदान स्थानीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवंटित किया जाएगा

गांधीनगर, 31 दिसंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वग्राही तथा सर्वसमावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण जन हितकारी निर्णय किए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से राज्य की सभी 34 जिला पंचायतों के अध्यक्षों को 1 करोड़ रुपए का विवेकाधीन अनुदान सम्बद्ध जिलों के स्थानीय महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए आवंटित करने के दिशानिर्देश दिए हैं।

राज्य में विधायकों को विकेन्द्रित जिला योजना कार्यक्रम अंतर्गत

विकास कार्यों के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान आवंटित करने की परंपरा है।

मुख्यमंत्री के समक्ष जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपने जिले में ग्रामीण विकास कार्यों को वेग मिले और स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जा सके; इस आशय से जिला पंचायत अध्यक्षों को भी विवेकाधीन अनुदान आवंटित करने की प्रस्तुतियाँ-मांग की थीं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन प्रस्तुतियों पर सकारात्मक तथा त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए यह एक करोड़ रुपए का विवेकाधीन अनुदान जिला पंचायत अध्यक्ष को आवंटित करने के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को दिया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। एक्स प्लेटफार्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा 'जय श्री राम! आज ही की शुभ तिथि पर दो वर्ष पूर्व 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की। प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगाँठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। प्रभु श्रीराम के आदर्शों और जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रतीक यह मंदिर धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष, सांस्कृतिक स्वाभिमान के लिए त्याग व विरासतों के संरक्षण के लिए बलिदान की अप्रतिम प्रेरणा बना रहेगा।

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल के अंतिम दिन महाराष्ट्र में किसानों से किया संवाद और नए साल के पहले दिन ग्रामीणों से करेंगे सीधा संवाद

साल के अंतिम दिन केन्द्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से किया संवाद
नए वर्ष के पहले दिन शिवराज सिंह करेंगे ग्रामीणों से चर्चा
कृषि- किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

(जीएनएस)।

नई दिल्ली- केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र प्रवास के दौरान अहिल्यानगर के बालेश्वर में कृषि विकास केन्द्र का भ्रमण कर किसानों से संवाद किया। शिवराज सिंह ने साल के अंतिम दिन खेत-खलिहान से जुड़े मुद्दों पर

किसानों के साथ संवाद करते हुए केन्द्रीय मंत्री हितग्राहियों को हितलाभ

कहा कि, केंद्र सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। साथ ही भी वितरित किए।

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और किसान उसके प्राण। किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। शिवराज सिंह ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

साल के पहले दिन करेंगे ग्रामीणों से चर्चा

वहीं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नए साल के पहले दिन, 1 जनवरी को ग्राम लोणी बुदरुक में ग्राम सभा कार्यक्रम में शामिल होंगे और ग्रामीणों से संवाद करेंगे, जहां गांवों के विकास, रोजगार, कृषि, सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विषयों पर केन्द्रीय मंत्री चर्चा करेंगे।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने भारत सरकार के कैलेंडर 2026 का अनावरण किया

कैलेंडर का विषय है "भारत@2026: सेवा, सुशासन और समृद्धि"
सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू ने कहा कि भारत@2026 कैलेंडर भारत की बदलती तस्वीर को प्रदर्शित करता है

(जीएनएस)।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज भारत सरकार के कैलेंडर 2026 का अनावरण किया। इस अवसर पर डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि यह कैलेंडर केवल तारीखों और महीनों का वार्षिक प्रकाशन मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो भारत की परिवर्तनकारी यात्रा को दशार्ता है, गवर्नेंस की प्राथमिकताओं को उजागर करता है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हमारे सामूहिक संकल्प को नया उत्साह प्रदान करता है।

कैलेंडर का विषय "भारत@2026: सेवा, सुशासन और समृद्धि", एक ऐसे भारत को प्रस्तुत करता है जो अपनी पहचान के प्रति सुरक्षित है, अपनी संस्थाओं में मजबूत है और अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण में स्पष्ट है। डॉ. एल. मुरुगन ने इस बात पर जोर दिया कि यह कैलेंडर देश के आत्मविश्वास की उस भावना को दशार्ता है, जो जन-केंद्रित शासन, मजबूत सर्विस डिलीवरी और उन सुधारों पर आधारित है जिन्हें प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नागरिकों एवं सरकार के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

वर्ष 2025 में किए गए प्रमुख सुधारों का उल्लेख करते हुए, डॉ. मुरुगन ने कहा कि संरचनात्मक उपायों ने भारत की आर्थिक मजबूती को बढ़ाया है और यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने उल्लेख किया कि नई कर व्यवस्था के तहत कर राहत, जीएसटी 2.0 को सरल बनाने, चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन और केंद्रित रोजगार सृजन पहल ने उत्पादकता, जीवन की सुगमता और समावेशी समृद्धि को गति प्रदान की है।

इस अवसर पर बोलते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री संजय जाजू ने कहा कि भारत सरकार का कैलेंडर वास्तव में सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है और यह एक शक्तिशाली संचार माध्यम के रूप में विकसित हुआ है, जो राष्ट्र की प्राथमिकताओं और मूल्यों को दशार्ता है।

आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) भारत में आईस्टेंट के साथ पहली 3डी फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी की

(जीएनएस)।

दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) के नेत्र रोग विभाग ने भारतीय चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए उन्नत इमेजिंग तकनीक और न्यूनतम चीर-फाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी को मिलाकर भारत में पहली बार आईस्टेंट के साथ 3डी फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक संपन्न की है। नए स्टैंड-माउंटेड स्पेक्ट्रालिस सिस्टम और अत्याधुनिक 3डी ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से संचालित यह अभूतपूर्व प्रक्रिया सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं को वैश्विक नेत्र चिकित्सा देखभाल में अग्रणी स्थान पर रखती है।

ग्लूकोमा, जो अपूरणीय अंधापन का एक प्रमुख कारण है, अपनी धीमी प्रगति के कारण लंबे समय से चिकित्सकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यह अभूतपूर्व तकनीक जलीय द्रव प्रवाह मार्गों का अभूतपूर्व वास्तविक समय दृश्य प्रदान करती है, जिससे सर्जन सटीक और लक्षित उपचार कर सकते हैं और रोगियों के उपचार में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं।

देश में अपनी तरह की पहली पहल के रूप में न्यूनतम चीर-फाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी, आईस्टेंट के साथ 3डी फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी का एकीकरण ग्लूकोमा के उपचार में एक नया मानदंड स्थापित करता है, जिससे ऑपरेशन के दौरान बेहतर इमेजिंग और दीर्घकालिक बेहतर परिणाम सुनिश्चित होते हैं। सशस्त्र बलों के लिए यह न केवल एक चिकित्सा उपलब्धि है बल्कि दृष्टि सुरक्षा और परिचालन तत्परता में एक रणनीतिक छलांग भी है।

एमसीए 03 नए क्षेत्रीय निदेशालय (आरडी) और 6 नए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) को नियुक्त करेगा

(जीएनएस)।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के निरंतर प्रयास के अंतर्गत, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय 16 फरवरी, 2026 से 03 क्षेत्रीय निदेशालय (आरडी) और 06 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) खोलेगा। इससे रेगुलेटरी सुविधा मिलेगी और साथ ही तेजी से बढ़ते व्यापार माहौल को जरूरी प्रोत्साहन भी मिलेगा।

मौजूदा उत्तर क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशालय, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और जिसके अधिकार क्षेत्र में एनसीटी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड राज्य और चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उसे दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। आरडी (एनआर-क) का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसके अधिकार क्षेत्र में एनसीटी दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य आएंगे। आरडी (एनआर-कक्र) का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा और इसके अधिकार क्षेत्र में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड राज्य और चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आएंगे।

मौजूदा आरओसी, दिल्ली जिसका अधिकार क्षेत्र एनसीटी दिल्ली और हरियाणा में था, उसे 03 आरओसी में बांटा गया है। आरओसी (एनसीटी ऑफ दिल्ली-क) का मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली और दिल्ली पूर्व जिलों पर होगा; आरओसी (एनसीटी ऑफ दिल्ली-कक्र) का मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र सेंट्रल दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली और शाहदरा जिलों पर होगा। आरओसी (हरियाणा), जो चंडीगढ़ में होगा, उसका अधिकार क्षेत्र हरियाणा के सभी जिलों पर होगा झ पहले, आरओसी (दिल्ली) का अधिकार क्षेत्र हरियाणा पर भी था। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश के 17 सबसे पश्चिमी जिलों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला आरओसी, नोएडा मौजूदा आरओसी, कानपुर से अलग किया जा रहा है।

मौजूदा पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशालय, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे महाराष्ट्र, गोवा राज्य और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश पर है, उसे दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। आरडी (डब्ल्यूआर-क) जिसका मुख्यालय मुंबई में होगा, उसका अधिकार क्षेत्र मुंबई, मुंबई उप शहरी जिलों, गोवा राज्य और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश पर होगा। आरडी (डब्ल्यूआर-कक्र) जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में होगा, उसका अधिकार क्षेत्र मुंबई और मुंबई उप शहरी को छोड़कर महाराष्ट्र के सभी जिलों पर होगा।

मौजूदा आरओसी, मुंबई को 02 आरओसी में बांटा गया है। आरओसी, मुंबई-क का मुख्यालय मुंबई में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र मुंबई और मुंबई उप शहरी जिलों पर होगा। आरओसी, मुंबई-कक्र का मुख्यालय नवी मुंबई में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र औरंगाबाद, धुले, जलगांव, नंदुरबार, नासिक, पालघर, रायगढ़ और ठाणे जिलों पर होगा। इसके अतिरिक्त, आरओसी, नागपुर की स्थापना की जा रही है, जिसका अधिकार क्षेत्र विदर्भ के 11 जिलों और मराठवाड़ा क्षेत्र के 7 जिलों पर होगा। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र (एसडब्ल्यूआर) के लिए एक नया क्षेत्रीय निदेशालय बनाया गया है, जिसका मुख्यालय बैंगलोर में होगा और इसके अधिकार क्षेत्र में कर्नाटक राज्य, केरल राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश आएंगे।

मौजूदा आरओसी, कोलकाता को 02 आरओसी में बांटा गया है। आरओसी, कोलकाता-क का मुख्यालय कोलकाता में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र कोलकाता जिले और सिक्किम राज्य पर होगा।

भारत सरकार के खातों की वित्त वर्ष 2025-26 के नवंबर माह तक की मासिक समीक्षा

(जीएनएस)।

भारत सरकार के नवंबर 2025 तक के मासिक खातों का संकलन कर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

सरकार को नवंबर 2025 तक 19,49,239 करोड़ रुपए (वर्ष 2025-26 के संबंधित वर्ष की कुल प्राप्तियों का 55.7 प्रतिशत) प्राप्त हुए हैं, जिसमें 13,93,946 करोड़ रुपए कर राजस्व (केंद्र को प्राप्त शुद्ध राशि), 5,16,366 करोड़ रुपए गैर-कर राजस्व और 38,927 करोड़ रुपए गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को करों में हिस्सेदारी के रूप में 9,36,561 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,24,498 करोड़ रुपए अधिक है।

भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 29,25,910 करोड़ रुपए (वर्ष 2025-26 के संबंधित बजट अनुमान का 57.8 प्रतिशत) है। इसमें से 22,67,700 करोड़ रुपए राजस्व मद के अंतर्गत तथा 6,58,210 करोड़ रुपए पूंजीगत मद के अंतर्गत व्यय किए गए है। कुल राजस्व व्यय में से 7,45,765 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान के रूप में तथा 2,88,333 करोड़ रुपए प्रमुख सब्सिडी के मद में व्यय किए गए है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 3 जनवरी 2026 को पिपरावा के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे

'लोटस लाइट: रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन' में प्रत्यावर्तित अवशेषों और संबंधित प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा

(जीएनएस)।

संस्कृति मंत्रालय "लोटस लाइट: रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन" शीर्षक से एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जिसमें पूजनीय पिपरावा अवशेषों के साथ-साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी बुद्ध की शिक्षाओं के साथ भारत के अटूट सभ्यतागत संबंध और अपनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और प्रस्तुति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

इस प्रतिष्ठित प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित राय पिथोरा सांस्कृतिक परिसर में किया जाएगा। यह आयोजन भारत के सांस्कृतिक और राजनयिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि प्रदर्शित अवशेषों में अत्यधिक ऐतिहासिक, पुरातात्विक और आध्यात्मिक महत्व के प्रत्यावर्तित पवित्र अवशेष शामिल हैं, जिनका विश्व भर के बौद्ध समुदायों द्वारा सम्मान किया जाता है।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खोजे गए पिपरावा अवशेषों को व्यापक रूप से गौतम बुद्ध के पार्थिव अवशेषों से संबंधित माना जाता है, जिन्हें शाक्य वंश द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। इनका प्रत्यावर्तन और सार्वजनिक प्रदर्शन भारत द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने और बुद्ध की शिक्षाओं में निहित शांति, करुणा और ज्ञान के सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों को दशार्ता है।

इस प्रदर्शनी में शामिल होंगी:

पवित्र पिपरावा अवशेष और संबंधित प्राचीन वस्तुएं

इनके ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक संदर्भों को उजागर करने वाली सुनियोजित प्रदर्शनियां

भारत को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल बताते हुए व्याख्यात्मक कथाए

यह प्रदर्शनी विद्वानों, भक्त तों और आम जनता सभी के लिए सोच-समझकर तैयार की गई है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने त्वरित अंतराल में दो प्रलय मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया

(जीएनएस)।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन-डीआरडीओ ने 31 दिसंबर, 2025 को दिन में लगभग 10 बजकर तीस मिनट पर ओडिशा तट के पास एक ही लॉन्चर से दो प्रलय मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया। ये परीक्षण उपयोगकर्ता मूल्यांकन के तहत किए गए। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के ट्रैकिंग सेंसरों से पुष्टि हुई कि दोनों मिसाइलों ने निर्धारित पथ का अनुसरण कर सभी उड़ान उद्देश्यों को पूरा किया। प्रक्षेपण बिंदुओं के निकट तैनात जहाज पर लगे टेलीमेट्री सिस्टम से भी इसकी पुष्टि हुई।

प्रलय स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें उच्च भेदक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन तकनीक का उपयोग किया गया है। यह मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों तक कई प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है।

प्रलय मिसाइल को मिसाइल प्रणाली और वैमानिकी के उन्नत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं (रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला, शस्त्र अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला, टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (इंजीनियर) और एकीकृत परीक्षण रेंज), विकास-सह-उत्पादन साझेदारों (भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) और अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से विकसित किया है। परीक्षणों के लिए, दोनों विकास-सह-उत्पादन साझेदारों ने प्रणालियों को एकीकृत किया। परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के उपयोगकर्ता प्रतिनिधि, और विकास-सह-उत्पादन साझेदारों सहित उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने त्वरित अंतर पर मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण पर डीआरडीओ, भारतीय वायु सेना, भारतीय सेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रलय मिसाइल के साल्वो प्रक्षेपण ने मिसाइल की विश्वसनीयता को स्थापित कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में 'साल्वो लॉन्च' का मतलब होता है. एक साथ या बहुत कम अंतर पर कई हथियारों से हमला।

भारतीय वायुसेना के उप-प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी सेवानिवृत्त हुए

(जीएनएस)।

एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी 31 दिसंबर 2025 को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के उप वायु सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्होंने राष्ट्र की चार दशकों तक गौरवशाली सेवा की है।

एयर मार्शल तिवारी 7 जून 1986 को भारतीय वायु सेना की लड़ाकू विमान शाखा में फ्लाइंग पायलट के रूप में कमीशन हुए । विभिन्न प्रकार के विमानों पर 3600 घंटे से अधिक के उड़ान अनुभव के साथ, एयर मार्शल ने विविध स्टाफ और कमांड पदों पर कार्य किया है। एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और प्रायोगिक टेस्ट पायलट होने के अलावा, एयर मार्शल अमेरिका के एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के स्नातक हैं। अपने शानदार सैन्य करियर के दौरान, उन्होंने

वेलिंगटन में भारतीय वायु सेना के टेस्ट पायलट स्कूल और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में डायरेक्टिंग स्टाफ के रूप में कार्य किया। उनके व्यापक फील्ड अनुभव में विभिन्न हथियारों और प्रणालियों का परिचालन परीक्षण शामिल है, जिसमें 1999 में कारगिल ऑपरेशन के दौरान 'लाइटनिंग' लेजर डेजिग्नेशन पॉड का संचालन भी शामिल है। वे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उड़ान परीक्षण के विभिन्न चरणों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। एयर मार्शल ने 2013 से 2016 तक पेरिस में एयर अताशे के रूप में कार्य किया। भारतीय वायु सेना में अपने करियर के दौरान, उन्होंने सहायक चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (प्रोजेक्ट्स), सहायक चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (प्लान्स), एयर हेडक्वार्टर (वीबी) में डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पदों पर कार्य किया।

उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में, एयर मार्शल तिवारी को परम विशिष्ट सेवा पदक (2025), अति विशिष्ट सेवा पदक (2022) और वायुसेना पदक (2008) से सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 में संचालन में विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से अलंकृत किया गया।

वर्ष 2025 की समीक्षा: वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक नेतृत्व को समर्पित वर्ष

(जीएनएस)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रमुख पहलें, सुधार और उपलब्धियां

1. वन संरक्षण, वृक्षारोपण और हरित आवरण संवर्धन

1.1 एक पेड़ मां के नाम अभियान

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान विश्व के सबसे बड़े जन-केंद्रित पर्यावरण आंदोलनों में से एक बनकर उभरा। इसे सरकार और समाज के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।

24 दिसंबर 2025 तक 262.4 करोड़ पौधे लगाए गए।

इस अभियान में भावनात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों को एकीकृत किया गया।

मेरी लाइफ पोर्टल के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को डिजिटल रूप से ट्रैक किया गया।

1.2 वन और वृक्ष आवरण की स्थिति

भारत की वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 के अनुसार:

देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत भाग वनों और वृक्षों से आच्छादित है (जिसमें 21.76 प्रतिशत वन क्षेत्र और 3.41 प्रतिशत वृक्ष क्षेत्र शामिल हैं)।

वर्ष 2013 से अब तक वन और वृक्ष आवरण में कुल मिलाकर 4.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एफएओ के वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार:

ध भारत वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर है (पहले 10वें स्थान पर था)।

ध वार्षिक शुद्ध वन वृद्धि में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान बरकरार रखता है।

ये उपलब्धियां वनों की गुणवत्ता में सुधार करते हुए हरित आवरण को बढ़ाने के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

1.3 राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय सीएएमपीए)

राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण ने अपनी नीतियों और नवोन्मेषी डिजिटल सुधारों के माध्यम से भारत में क्षतिपूर्ति वनीकरण और इको-सिस्टम सेवाओं की बहाली की गतिविधियों की योजना और प्रबंधन में परिवर्तन किया है।

मजबूत वित्तीय तंत्र, बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक बहाली और नई डिजिटल प्रणालियों को मिलाकर—जैसे कि (1) अखिल भारतीय डिजिटल एपीओ पोर्टल को शुरू करना, (2) बीआईएसएजी-एन के साथ संयुक्त रूप से निगरानी और मूल्यांकन उपकरण का विकास, और (3) राष्ट्रीय कैम्पा डैशबोर्ड—राष्ट्रीय सीएएमपीए पारदर्शिता, जवाबदेही और वैज्ञानिक निरीक्षण सुनिश्चित कर रहा है।

राष्ट्रीय प्राधिकरण सीएएमपीए ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 8561.34 करोड़ रुपये की वार्षिक परिचालन योजना को मंजूरी दे दी है ।

1.4 अरावली भूदृश्य बहाली (ग्रीन वॉल पहल)

अरावली ग्रीन वॉल पहल के तहत 6.31 मिलियन हेक्टेयर भूमि के पुनर्स्थापन का प्रस्ताव है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप क्षेत्र शामिल हैं।

एक चरणबद्ध पुनर्स्थापन योजना (2025-2034) सीएएमपीए, एमजीएनआरईजीएस, ग्रीन इंडिया मिशन और अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय के माध्यम से वन पुनर्स्थापन, घास के मैदानों के पुनरुद्धार और खदानों के पुनर्ग्रहण पर केंद्रित है।

2025 तक लगभग 36,025 हेक्टेयर क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया जा चुका है।

अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चार राज्यों में फैली 435 नर्सरियां स्थापित की गई हैं, जिनकी संयुक्त अनुमानित उत्पादन क्षमता 393.24 लाख पौधों की है।

अरावली पर्वत श्रृंखला को पुनर्स्थापित करने की एक प्रमुख पहल, अरावली भूदृश्य बहाली के लिए एक विस्तृत कार्य योजना का अनावरण 21 मई 2025 को किया गया। यह कार्य योजना अरावली की पारिस्थितिक अखंडता को बहाल करने के लिए विज्ञान-आधारित, समुदाय-नेतृत्व वाली और नीति-समर्थित कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

2. वन्यजीव संरक्षण और प्रजाति पुनर्प्राप्ति

2.1 प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट

भारत ने अपने प्रमुख संरक्षण कार्यक्रमों को और मजबूत करने की नीति को जारी रखा:

अब 58 टाइगर रिजर्व लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जबकि 2014 में इनकी संख्या 46 थी।

नया अभ्यारण्य: माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश।

अखिल भारतीय बाघ आकलन का छठा चक्र शुरू किया गया (वैश्विक स्तर पर पहली बार)।

पयार्वास सुधार और गलियारों के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई।

हाथी अभ्यारण्यों की संख्या 2014 में 26 की तुलना में 2025 में बढ़कर 33 हो गई; लगभग 8,610 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षण के अंतर्गत लाया गया।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

नव वर्ष 2026 का शुभारम्भ

स्वागत है 2026! वर्ष 2025 का समापन और 2026 का शुभारंभ हो गया है। व्यक्तिगत रूप से वुछ लोगों के लिए वर्ष 2025 अच्छा रहा होगा और वुछ लोगों के लिए अत्यन्त दुखद। वुछ लोगों के लिए गत वर्ष मिश्रित रहा होगा किन्तु यदि देश के स्तर पर बात की जाए तो वर्ष 2025 वुछ मामलों में तो अच्छा रहा जैसे आर्थिक विशेष रूप से विकास दर को लेकर भारत की आर्थिक मोच्रे पर प्रागति को देखकर कई देशों ने अपनी आर्थिक रणनीति में बदलाव कर लिया। ब्रिटेन और प्रांस को तो पहले ही पछाड़ दिया था भारत ने लेकिन 2025 में भारत जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। दुनिया की रेटिग एजेंसी भारत की जीडीपी को 7 प्रातिशत से ज्यादा नहीं आंक रही थी किन्तु वास्तव में यह आंकड़ा 8.2 प्रातिशत का निकला। भारत तकनीकी एवं रक्षा उत्पादन में चौथे स्थान पर खड़ा है। इन सभी के बावजूद वर्ष 2025 में ही पाकिस्तान की आतंकी साजिश का शिकार कश्मीरी पर्यंटन विभाग को भी नहीं भूला जा सकता। पाकिस्तान ने जब देखा कि कश्मीर में लगातार पर्यंटकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है तो उसने पहलगाम में पर्यंटकों पर हमला करा दिया इससे 25 लोग मारे गए। आतंकी हमले तो असंख्य वार हुए हैं कश्मीर में किन्तु 1989 के बाद यह पहली बार हुआ है जब धर्म पूछकर पर्यंटकों को गोली मारी गई। इसी वजह से पाकिस्तान की इस हरकत से भारत में अत्यन्त आव्रोश व्याप्त हो गया। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिन्दूर चलाकर पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने तब खुल गई जब आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के राजनेता और शीर्ष सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। पाकिस्तान अपने देश के आतंकी ठिकानों को अपने लिए घातक नहीं मानता। इस्लामाबाद का मानना है कि जितने भी आतंकी गिरोह हैं वे सभी पाकिस्तान के लिए हीरों हैं। दुनिया की हर सेना में तीन विग होती हैं किन्तु पाकिस्तान में 4 होती हैं। चौथी शाखा फिदायीन की होती है और उनकी भता, ट्रेनिग तथा ऑपरेशन की जिम्मेदारी इन्हीं आतंकी संगठनों की होती हैं जिन्हें पाकिस्तान की फौज मोटी वित्तीय मदद करती है। पाकिस्तान बारबार एफएटीएफ की ग्रो लिस्ट में शामिल होता है फिर दो-एक सरगना को हाउस अरेस्ट करके इस बात का दिखावा करता है कि वह अब आतंकियों को नियंत्रित करेगा और वुछ समय बाद फिर से आतंकियों का वित्त पोषण शुरू कर देता है। 2025 में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसके तमाम सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। पाकिस्तान ने भी चीनी की मदद से भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया किन्तु एस-400 डिपेंस सिस्टम की मदद से भारत ने शत्रु देश के हर हमलों को असफल करने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया कि भारत के पास अपार रक्षा संसाधन हैं और खुलकर कोई देश अपनी सेना और युद्धक विमान देकर उसकी सहायता नहीं करेगा। लजिस्टिक सपोर्ट तो चीन और तुका दोनों ने दी किन्तु पाकिस्तान को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि किसी देश ने युद्धक पाकिस्तान की वैसी मदद नहीं की जैसा कि वह चाहता था। बहरहाल 2025 में भारत और पाक ने एक-दूसरे की क्षमता का एहसास किया। लेकिन दोनों ने समझदारी दिखाकर युद्ध को 48 घंटे में ही समाप्त करके बहुत समझदारी का काम किया अन्यथा यदि दोनों देश युद्ध में पंस जाते तो दोनों देशों का ही बंटाधार होता। बहरहाल वर्ष 2025 में ही अन्य आतंकी घटनाओं में लालकिले का हमला भी शामिल था जिसमें लोगों की जान बचाने वाले ईश्वर का दूसरा रूप माने जाने वाले डाक्टर ही बारूदी खेल में शामिल थे। इसके अलावा तमाम दुर्घटनाएं हुईं। 2025 भारत का अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर संबंधों में तनाव के लिए भी जाना जाएगा। किन्तु इन सभी अशुभ घटनाओं का अंधेरी रात के बाद सवेरा होना निाति है इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्ष 2026 सुखद, समृद्ध और सशक्त भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए माना जाए। दुनिया में जितने भी देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वे संयम और समझ से काम लेंगे और विश्व बंधुत्व के महत्व को महसूस करेंगे तभी "सव्रे भवन्तु सुखिनः सव्रे सन्तु निरामयाः"

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में बीओटी मोड पर 374 किलोमीटर लंबे और 19,142 करोड़ रुपये की लागत वाले 6 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण वाली परियोजना को मंजूरी दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज महाराष्ट्र में बीओटी मोड पर 374 किलोमीटर लंबी और 19,142 करोड़ रुपये की कुल लागत से निर्मित होने वाली छह लेन की ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना नासिक, अहिल्यानगर और सोलापुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों को कुरनूल से जोड़ेगी, जैसा कि मानचित्र में दशार्या गया है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सिद्धांत के तहत एकीकृत परिवहन अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

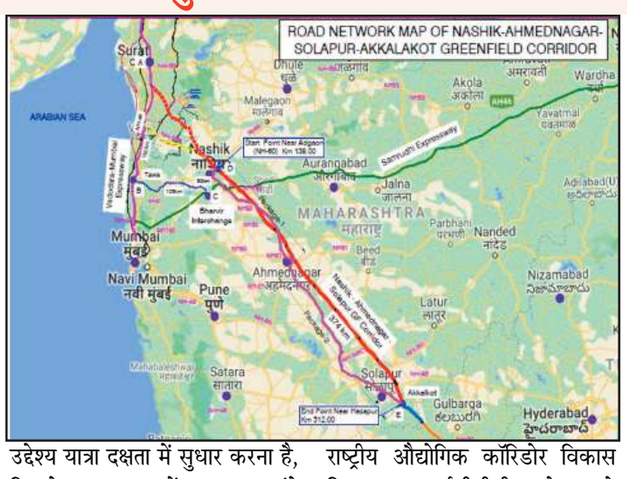

नासिक से अक्कलकोट तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को वधावन बंदरगाह इंटरचेंज के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, नासिक में एनएच-60 (अदेगांव) के जंक्शन पर आगरा-मुंबई कॉरिडोर और पांगरी (नासिक के पास) में समृद्धि महामार्ग से जोड़ा जाना है। प्रस्तावित कॉरिडोर पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। चेन्नई बंदरगाह से की ओर से तिरुवल्लूर, रेनिगुंटा, कडप्पा और कुरनूल होते हुए चेन्नई से हसापुर (महाराष्ट्र सीमा) तक लगभग 4-लेन कॉरिडोर परियोजनाएं (700 किमी लंबा) पहले से ही निमार्णाधीन है। प्रस्तावित एक्सेस-नियंत्रित छह-लेन ग्रीनफील्ड परियोजना कॉरिडोर का प्राथमिक

उद्देश्य यात्रा दक्षता में सुधार करना है, जिससे यात्रा समय में लगभग17 घंटे की कमी और यात्रा दूरी में 201 किमी की कमी होने की उम्मीद है। नासिक-अक्कलकोट (सोलापुर) कनेक्टिविटी कोप्पार्थी और ओरवाकल के प्रमुख राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (एनआईसीडीसी) नोड्स से शुरू और समाप्त होने वाले माल ढुलाई के लिए लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करेगी। इस खंड का नासिक-तलेगांव दिघे वाला हिस्सा पुणे-नासिक एक्सप्रेसवे के विकास की आवश्यकता को भी पूरा करता है, जिसे एनआईसीडीसी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में चिह्नित किया है। यह परियोजना बेहतर सुरक्षा और निर्बाध यातायात आवागमन के लिए डिजाइन किया गया एक उच्च गति कॉरिडोर प्रदान करती है, जिससे यात्रा का समय, भीड़भाड़ और परिचालन लागत कम होती है। इस परियोजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना से क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बेहतर होगा, जिससे नासिक, अहिल्यानगर, धराशिव और सोलापुर जिलों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

यह छह लेन का एक्‍ सेस-कंट्रोल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर क्‍ लोज टोलिंग प्रणाली के साथ विकसित किया गया है, जो औसतन 60 किमी/घंटे की वाहन गति तथा 100 किमी/घंटे की डिजाइन गति को समर्थन देगा। इससे कुल यात्रा समय लगभग 17 घंटे तक कम हो जाएगा (31 घंटे का 55 प्रतिशत रह जाएगा), साथ ही यात्री और मालवाहक दोनों वाहनों के लिए सुरक्षित, तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

इस परियोजना से लगभग 251.06 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 313.83 लाख मानव-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। इसके अलावा, प्रस्तावित कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

ओडिशा में एनएच-326 के 68,600 किलोमीटर से 311,700 किलोमीटर तक मौजूदा 2-लेन सड़क को पक्की शोल्डर सहित 2-लेन सड़क में बदलने के लिए 1526.21 करोड़ रुपये की लागत से ईपीसी मोड पर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने ओडिशा में एनएच-326 के 68,600 किलोमीटर से 311,700 किलोमीटर तक मौजूदा 2-लेन सड़क को पक्की शोल्डर सहित 2-लेन सड़क में बदलने के लिए 1526.21 करोड़ रुपये की लागत से ईपीसी मोड पर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी

प्रविष्टि तिथिः 31 उएउ 2025 3:14ढट ु८ ढक्ह ऊ॑

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ओडिशा राज्य में एनएच-326 के 68,600 किलोमीटर से 311,700 किलोमीटर तक मौजूदा 2-लेन को पेव्ड शोल्डर (सड़क के किनारे बनी पक्की, समतल पट्टी) सहित 2-लेन में बदलने और मजबूत करने को एनएच(ओ) के तहत ईपीसी मोड (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन परियोजना वितरण पद्धति) की मंजूरी दी।

वित्तीय निहितार्थः

इस परियोजना की कुल पूंजी लागत 1,526.21 करोड़ रुपये है। इसमें 966.79 करोड़ रुपये की सिविल निर्माण लागत शामिल है।

फायदेः

एनएच-326 के उन्नयन से यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय हो जाएगी। इससे दक्षिणी ओडिशा का समग्र विकास होगा, विशेष रूप से गजपति, रायगड़ा और कोरापुट जिलों को लाभ मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय समुदायों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और पर्यटन केंद्रों को बाजारों, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। इससे क्षेत्र के समावेशी विकास में योगदान मिलेगा।

विवरणः

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-326) का मोहना-कोरापुट खंड (मध्यवर्ती लेन/दो लेन, कई दोषपूर्ण मोड़ और तीव्र ढलान) के कारण वर्तमान में निम्न गुणवत्ता का है। इसका मौजूदा सड़क संरेखण, मार्ग की चौड़ाई और ज्यामितीय कमियां भारी वाहनों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही में बाधा डालती हैं। इसके कारण तटीय बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों तक माल ढुलाई प्रभावित होती है। कॉरिडोर को दो लेन में अपग्रेड करके, पेव्ड शोल्डर बनाकर, ज्यामितीय सुधार (मोड़ का पुनर्संरेखण और ढलान में सुधार), ब्लैक स्पॉट को हटाकर और सड़क को मजबूत करके इन बाधाओं को दूर किया जाएगा। इससे माल और यात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही संभव होगी और वाहन संचालन लागत में कमी आएगी।

इसके उन्नत किये जाने से मोहना-कोरापुट से प्रमुख आर्थिक और साजो-सामान गलियारे तक सीधी और बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। यह जो एनएच-26, एनएच-59, एनएच-16 और रायपुर-विशाखापत्तनम गलियारे से जुड़ेगी और गोपालपुर बंदरगाह, जेपोर हवाई अड्डे और कई रेलवे स्टेशनों तक सबके लिए पहुंच में सुधार करेगी। यह कॉरिडोर महत्वपूर्ण औद्योगिक और साजो-सामान केंद्रों (जेके पेपर, मेगा फूड पार्क, नालको, आईएमएफए, उत्कल एल्युमिना, वेदांता, एचएएल) और शिक्षा/पर्यटन केंद्रों (ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट मेडिकल कॉलेज, तप्तपानी, रायगड़ा) को जोड़ता है। इससे माल ढुलाई में तेजी आएगी, यात्रा का समय कम होगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

यह परियोजना दक्षिणी ओडिशा (गजपति, रायगड़ा और कोरापुट जिले) की है और इससे वाहनों की आवाजाही को तेज और सुरक्षित बनाकर राज्य के भीतर और अंतर-राज्यीय संपर्क को काफी हद तक सुधारने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह परियोजना औद्योगिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा देगी तथा आकांक्षी और आदिवासी क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच में सुधार करेगी। आर्थिक विश्लेषण से पता चलता है कि परियोजना का ईआईआरआर 17.95 प्रतिशत (आधार स्थिति) है, जबकि वित्तीय प्रतिफल (एफआईआरआर) नकारात्मक (-2.32 प्रतिशत) है। यह आर्थिक मूल्यांकन में शामिल सामाजिक और गैर-बाजार लाभों को दशार्ता है। इसमें मुख्य रूप से यात्रा समय और वाहन परिचालन लागत में बचत तथा सुरक्षा लाभ (ज्यामितीय सुधारों के बाद मोहना और कोरापुट के बीच लगभग ढाई से तीन घंटे तक की अनुमानित यात्रा समय में बचत और लगभग 12.46 किमी की दूरी की बचत) शामिल हैं।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्यः

यह कार्य ईपीसी मोड में पूरा किया जाएगा। ठेकेदारों को पुख्ता निर्माण और गुणवत्ता आश्वासन प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा। इनमें पूर्वनिर्मित बॉक्स-प्रकार संरचनाएं और पूर्वनिर्मित नालियां, पुलों और ग्रेड विभाजकों के लिए पूर्वनिर्मित आरसीसी/पीएससी गर्डर, प्रबलित मिट्टी की दीवारों पर पूर्वनिर्मित क्रैश बैरियर और फ्रिक्शन स्लैब और फुटपाथ परतों में सीमेंट ट्रीटेड सब-बेस (सीटीएसबी) शामिल किये जा सकते हैं। गुणवत्ता और प्रगति का सत्यापन नेटवर्क सर्वे व्हीकल (एनएसवी) और आवधिक ड्रोन-मैपिंग जैसे विशेष सर्वेक्षण और निगरानी उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा। दैनिक पर्यवेक्षण नियुक्त प्राधिकरण अभियंता द्वारा किया जाएगा और परियोजना की निगरानी परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) के माध्यम से की जाएगी।

प्रत्येक पैकेज के लिए निर्धारित तिथि से 24 महीनों में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद पांच वर्ष की दोष दायित्व/रखरखाव अवधि होगी (कुल अनुबंध अवधि 7 वर्ष की होगीः 2 वर्ष निर्माण + 5 वर्ष दोष दायित्व/रखरखाव)। वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त होने और आवश्यक भूमि पर कब्जा मिलने के बाद अनुबंध प्रदान किया जाएगा।

रोजगार सृजन की क्षमता सहित प्रमुख प्रभावः

इस परियोजना का उद्देश्य यातायात की सुगम और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना तथा ओडिशा के दक्षिणी और पूर्वी भागों के बीच संपर्क को बेहतर बनाना है। विशेष रूप से गजपति, रायगढ़ा और कोरापुट जिलों को राज्य के शेष भाग और पड़ोसी आंध्र प्रदेश से जोड़ना इसका लक्ष्य है। बेहतर सड़क नेटवर्क से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी तथा दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

निर्माण और रखरखाव अवधि के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों से कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। यह परियोजना निर्माण

ईएसआईसी ने नियोक्ताओं को पिछली देनदारियों के बिना शामिल होने के लिए अधिक समय दिया

-2025 की समय सीमा 31 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गईः स्प्री-2025 में एक महीने का विस्तार ईएसआईसी के समावेशी और सरलीकृत अनुपालन के प्रयासों को और मजबूत करता है

(जीएनएस)।

नियोक्ताओं, नियोक्ता संघों और राज्य सरकारों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहन देने की योजना स्प्रीझ2025 (एसपीआरईई 2025), को ईएसआईसी द्वारा शुरू किया गया था। इसके संचालन की अवधि 1 जुलाई, 2025 से 31 दिसंबर तक थी। अब इसे 01.01.2026 से 31.01.2026 तक एक महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

एसपीआरईई योजना को शिमला में आयोजित ईएसआई निगम की 196वीं बैठक में मंजूरी दी गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की। इस योजना का उद्देश्य ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाना है। यह योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को बिना किसी निरीक्षण या पूर्व बकाया या रिकॉर्ड की मांग का सामना किए ईएसआई सुविधाओं का लाभ लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।

इस विस्तार के साथ, नियोक्ताओं को ईएसआईसी, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टलों के माध्यम से अपने व्यवसायों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। पंजीकरण नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगा। जो प्रतिष्ठान पहले पंजीकृत नहीं थे, उन्हें भी नई समयसीमा के भीतर पंजीकरण कराने पर 'पिछली अंशदान की मांग नहीं', निरीक्षण नहीं और पूर्व अभिलेखों की आवश्यकता नहीं होने का लाभ मिलेगा। यदि नियोक्ता एसपीआरईई योजना का लाभ उठाने में विफल रहता है और ईएसआई योजना के तहत अपने प्रतिष्ठान को पंजीकृत नहीं कराता है, तो ऐसे प्रतिष्ठान को 31.01.2026 के बाद कानूनी कार्रवाई और जुर्माने के अलावा हजार्ना और ब्याज सहित पिछली अंशदान राशि का भुगतान करना होगा।

स्प्री-2025 को 31 जनवरी, 2026 तक विस्तारित करना भारत में स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए ईएसआईसी की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। यह हाल ही में लागू की गई सामाजिक सुरक्षा संहिता के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है।

भारत ने वेव्स 2025 की मेजबानी की; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इस अग्रणी पहल में 90 से अधिक देश शामिल हुए

वर्षांत समीक्षा 2025 – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

क्रिएटोस्फीयर में 'क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस' – विभिन्न देशों के रचनाकारों को जोड़ना

वेवएक्‍ स 2025: मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक अगली पीढ़ी का मंच

वेव्‍ स बाजार, भारत की रचनात्मक प्रतिभाओं और उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला एक ही स्थान पर सभी उत्पादों का पोर्टल

रचनात्मक प्रौद्योगिकियों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण के लिए आईआईसीटी ने नया राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया

(जीएनएस)।

वेव्स : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2025 में भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें कीं। इनमें सबसे बड़ी पहल विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्‍ स) 2025 था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍ द्र मोदी ने वेव्‍ स को महज एक आयोजन नहीं, बल्कि "संस्कृति, रचनात्मकता और सार्वभौमिक जुड़ाव की लहर" बताया और दुनिया भर के रचनाकारों को "बड़े सपने देखने और अपनी कहानी कहने" के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने "भारत में सृजन करो, दुनिया के लिए सृजन करो" के भारत के दृष्टिकोण पर भी जोर दिया और वैश्विक निवेशकों और युवाओं को भारत के विशाल रचनात्मक तंत्र से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया।

पीएलआई योजना ने 35,657 करोड़ रुपये के निवेश और 2,321.94 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन राशि के वितरण के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं

(जीएनएस)।

देश में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों में देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव-ऑटो योजना (पीएलआई ऑटो) शुरू की गई है। इस योजना का कुल बजटीय आवंटन 25,938 करोड़ रुपये है। यह वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि को कवर करती है।

पीएलआई-ऑटो योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 पहला प्रदर्शन वर्ष था तथा वित्त वर्ष 2024-25 में चार (4) अनुमोदित आवेदकों को 322 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई (अनुलग्नक की तालिका 1)।

आज तक, प्रदर्शन वर्ष 2024-25 के लिए कुल 1,999.94 करोड़ रुपये की राशि पांच (5) स्वीकृत आवेदकों को वितरित की जा चुकी है।

इस योजना के अंतर्गत कुल 10,42,172 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (ई-2डब्ल्यू), 2,38,385 इलेक्ट्रिक

तिपहिया वाहन (ई-3डब्ल्यू), 79,540 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (ई-4डब्ल्यू) और 1,391 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं (अनुलग्नक की तालिका 2)।

पीएलआई ऑटो योजना केवल उन्हीं उत्पादों को प्रोत्साहन देती है जो न्यूनतम 50 प्रतिशत का घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करते हैं। आज तक, चैंपियन ओईएम श्रेणी के अंतर्गत आठ (8) आवेदकों को 94 वेरिएंट के लिए घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जबकि कंपोनेंट चैंपियन श्रेणी के अंतर्गत दस (10) आवेदकों को 37 वेरिएंट के लिए घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणन प्राप्त हुआ है (अनुलग्‍ नक की तालिका 3 और 4) । पीएलआई ऑटो के आवेदक प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

इस योजना के अंतर्गत, 30 सितम्बर, 2025 तक 35,657 करोड़ रुपये का संचयी निवेश और 32,879 करोड़ रुपये की संचयी निर्धारित बिक्री की गई है। इसके अलावा, 48,974 लोगों के लिए रोजगार सृजित किया गया है। 31 दिसंबर, 2025 तक 2,321.94 करोड़ रुपये का संचयी प्रोत्साहन वितरित किया जा चुका है

उत्तराखंड मौसम : क्या नए साल में होगा बर्फबारी से स्वागत, कहां और कब, जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी

(जीएनएस)।

उत्तराखंड में नए साल का स्वागत कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी से हो सकता है। इस समय सबसे ज्यादा पर्यटक पहाड़ों की तरफ पहुंच रहे है। नए साल के जश्न के लिए टूरिस्ट प्लेस पैक हो गए हैं। सबको बर्फबारी का इंतजार है। बुधवार को मौसम सुबह से बदला हुआ नजर आया।

एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है, जिससे प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर से राज्य के उच्च हिमालयी जिलों-उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़-में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

इसके साथ ही गढ़वाल मंडल के अन्य क्षेत्रों जैसे देहरादून के पर्वतीय इलाके, टिहरी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जनपदों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम

वैज्ञानिकों के मुताबिक 3200 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना अधिक है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड और बढ़ सकती है। वहीं एक जनवरी को कुमाऊँ मंडल के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 3000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। नए साल की शुरूआत के साथ पहाड़ों में मौसम सुहावना लेकिन ठंडा रहने का अनुमान है।

दो जनवरी से मौसम की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना जताई गई है। इस दिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा मैदानी इलाकों-विशेषकर हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर-में घने कोहरे की आशंका बनी रहेगी, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है।

आने वाले दो दिनों में प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।

वित्त मंत्रालय की वर्ष 2025 के लिए वर्षान्त समीक्षाः लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

(जीएनएस)।

2025 में, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यान्वयन और पॉलिसी पहलों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कीं।

2025 के दौरान उपलब्धियों का एक प्रमुख आकर्षण चुने गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और अन्य संगठनों के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की सजग निगरानी और सुविधा थी। चुने गए सीपीएसई (जिनका सालाना कैपेक्स अनुमान ₹100 करोड़ या उससे अधिक है) और अन्य सरकारी संगठनों – जैसे रेलवे बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी), और दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) – के लिए कैपेक्स सफलता को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सितंबर 2025 के अंत तक इकट्ठा किया गया है। अप्रैल-सितंबर 2025 की अवधि के दौरान, इन संस्थाओं ने ₹3.85 लाख करोड़ का कैपेक्स प्राप्त किया, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹7.85 लाख करोड़ के वार्षिक बजट अनुमानों का 49.1% है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीपीएसई के लिए एक साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वर्कशॉप की एक सीरीज आयोजित करने की पहल की है।

मोहनलालगंज पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाया अज्जू हत्याकांड, आरोपी हुआ गिरफ्तार

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में पुलिस ने सनसनीखेज अज्जू हत्याकांड का मात्र 12 घंटे में खुलासा करते हुए तीन आरोपियों रमजान, अरमान और सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को लापता हुए अलमास सिद्दीकी उर्फ अज्जू का शव मंगलवार को मऊ नहर से बरामद हुआ था हत्या की वजहः पुलिस जांच में मामला एकतरफा प्रेम-प्रसंग की रंजिश का

निकला कैसे हुई गिरफ्तारी टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों और डिजिटल साक्ष्यों की मदद से हत्यारों को दबोच लिया बरामदगी हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा, मृतक का मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की गई है आरोपियों ने अज्जू के सिर पर वार कर हत्या की और साक्ष्य छिपाने के लिए शव नहर में फेंक दिया था पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय स्तर पर काफी सराहना हो रही है।

योगी सरकार के प्रयास से सनातन का लौटा वैभव, युवाओं में बढ़ा काशी, मथुरा और अयोध्या का क्रेज

(जीएनएस)।

लखनऊ। नए साल का जश्न मनाने के लिए जहां युवा पहले पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर

डिस्को, होटल, रेस्टोरेंट और हिल स्टेशनों का रुख करता था इस साल इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन के पौने नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है, उसका ही परिणाम है कि युवा लाखों की संख्या में काशी, मथुरा-वृंदावन और अयोध्या में नए साल की शुरूआत अपने इष्ट का दर्शन-पूजन से कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश से उठी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की वो लहर है, जिसमें न केवल प्रदेश बल्कि देशभर के युवा, लड़के-लड़कियां नए जोश और उत्साह के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार, इस वर्ष नए साल से कई दिन पहले से ही प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों काशी, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन और प्रयागराज में लाखों की संख्या में युवा पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस क्रम में 29-30 दिसंबर को ही अयोध्या में भगवान श्रीराम का दर्शन करने 5 लाख से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं, जबकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पिछले तीन दिनों में 10 लाख और मथुरा में 3 लाख से अधिक पर्यटकों ने दर्शन पूजन किया। इनमें युवा पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक है। 31 दिसंबर और 01 जनवरी को और अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं, साथ ही सुविधा के लिए गाइडलाइन भी जारी की है सोशल मीडिया पर भी छाया है शटैग न्यू ईयर 2026 इन अयोध्या पर

नए साल का जश्न धर्म स्थलों में मनाने का युवाओं का यह रुझान सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है। जहां न्यू ईयर 2026 इन अयोध्या, न्यू ईयर 2026 इन काशी या स्पिरिचुअल न्यू ईयर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। युवा नए साल के जश्न में इन धर्म स्थलों पर दर्शन पूजन कर, दोस्तों और परिवारजनों के साथ सेल्फी अपलोड कर रहे हैं। यही रुझान पिछले वर्ष प्रयागराज में आयोजित हुए दिव्य-भव्य महाकुंभ में भी देखने को मिला था, जिसमें न केवल देश बल्कि विश्व के कोने-कोने से श्रद्धालु और पर्यटकों ने आकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया

था। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश में धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ है, उसने युवाओं के मन में आध्यात्मिक उत्साह और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अलख जगाई है। इस संबंध में काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विश्व भूषण मिश्र का कहना है- सनातन संस्कृति उत्सव, उत्साह एवं उल्लास की आश्रयस्थली है। विश्व के समस्त उत्सव सनातन मान्यता में उत्कर्ष प्राप्त करते हैं। लोक उत्सव प्रायः तात्कालिक सत्ता के आचरण को प्रतिबिंबित करता है। अतः स्वाभाविक ही है कि वर्तमान काल में प्रत्येक पर्व पर चाहे वह भारतीय हो अथवा पश्चिम का पर्व, सनातन आस्था के केंद्रों पर श्रद्धालुओं का प्रवाह अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण और मथुरा-वृंदावन, तीर्थराज प्रयागराज, विंध्याचल, नैमिषारण्य, संभल, मुजफ्फरनगर में शुक्रतीर्थ (शुक्रताल) के साथ प्रदेश के पुरातन मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, इससे विशेष तौर पर युवाओं में सनातन संस्कृति और अपनी परंपराओं के प्रति नई को ऊर्जा का संचार हुआ। यह स्थान पहले की सरकारों में उपेक्षा का शिकार थे। प्रमुख तीर्थों और धार्मिक स्थलों तक सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के साथ वहां रुकने ठहरने, होटल और रेस्टोरेंट गतिविधियों का विकास हुआ है। यही नहीं जिस तरह से समय-समय पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की ओर से दिव्य-भव्य उत्सवों का आयोजन किया जाता है, उसने प्रदेश के युवाओं में सनातन संस्कृति के तीर्थों और धर्म स्थलों के प्रति आकर्षण बढ़ाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इन प्रयासों ने न केवल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया है, बल्कि युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर भी मिला है।

पिता ने अपनी पुत्री की हसिया से गला काटकर की हत्या वजीरगंज पुलिस ने किया खुलासा

दिनाक 29.12.2025 को उ0नि0 श्री सुपेन्द्र मलिक के मोबाइल नम्बर पर सूचना प्राप्त हुई की बहद जंगल ग्राम लहरा लाडपुर मे पूरनलाल पुत्र सुखलाल के खेत मे एक लडकी का शव पडा है उक्त सूचना पर इंचार्ज निरीक्षक अपराध श्री संजीव कुमार मय फोर्स के मौके पर पहुचे तथा तदोपरान्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक भी मौके पर आ गये तथा मृतका की पहचान सोनम पुत्री इकरार निवासी ग्राम लहरा लाडपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूं के रूप मे उसक पिता इकरार द्वारा की गयी पुलिस ने शव को कब्जा मे लेकर शव का का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बदायूं भेजा तथा मृतका उपरोक्त के पिता वादी मुकदमा श्री इकरार पुत्र अब्दुल गनी निवासी ग्राम लहरा लाडपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूं की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 405/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद पंजीकृत किया गया मुकदमा उपरोक्त मे मुखबिरान की सूचना व एकत्रित की गयी साक्ष्य व तकनीकी जानकारी से वादी मुकदमा द्वारा ही अपनी पुत्री की हत्या करना पाया जाने पर उसका नाम प्रकाश मे आया जिसके आधार पर आज दिनांक 31.12.2025 को समय 10.45 बजे सुरसैना भट्टे के पास से अभियुक्त इकरार उपरोक्त को गिरफ़्तार किया तथा अभियुक्त से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया की साहब मेरी पुत्री का चल चलन ठीक नही था वह कई बार घर से

चली गयी थी जिससे हम परिवार वाले काफी परेशान थे हमने अपनी पुत्री को काफी समझाया था तथा उसके साथ मारपीट भी की थी लेकिन वह नही मानती थी जिससे हमारी गांव मे बहुत बदनामी हो रही थी हमारा घर से निकलना दुसवार हो चुका था दिनाक 19/20.12.2025 रात्रि मे करीब 12 बजे मेरी पुत्री घर से चली गयी थी मै अपनी बदनामी से काफी परेशान था इसलिय मै अपने घर से हसिया लेकर अपनी पुत्री को तलाश करने निकाल गया की उसके मिलने पर उसको मार दूँगा मै अपनी पुत्री को तलाश करता हुआ गांव से कुछ ही दूरी पर ट्यूबवैल के पास पहुंचा तो मैने देखा की मेरी पुत्री ट्यूबेल पर बैठी थी मैने अपनी पुत्री से पूछा घर से क्यो आयी है तो मुझसे वहस करने लगी मुझे गुस्सा आ गया और मैने अपने हाथ मे हसिया से अपनी पुत्री की गर्दन काट दी और खून वही ट्यूबेल की नाली मे धो दिया और उसकी लाश को कधे पर रखकर गांव के पू रनलाल पुत्र सुखलाल के लहटे के खेत मे डाल दिया था और हसिया भी रात्रि के समय अंधेरे में खेतो मे फैक दिया था घना कोहरा व रात होने के कारण मुझे किसी ने नही देखा था मै चुप चाप अपने घर आकर सो गया था

मण्डलायुक्त ने संयुक्त रूप माघ मेला-2026 के दृष्टिगत तैयारियों का निरीक्षण कर जायजा लिया

(जीएनएस)।

मण्डलायुक्त श्रीमती सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा, मेलाधिकारी श्री ऋषिराज ने बुधवार को संयुक्त रूप से माघ मेला-2026 के दृष्टिगत हो रही तैयारियों का निरीक्षण कर जायजा लिया तथा सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सर्वप्रथम संगम नोज पर स्नानार्थियों के लिए बनाये जा रहे घाटों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने वहां पर सकुर्लेटिंग एरिया बढ़ाये जाने के कार्य व स्नान हेतु घाटों के विस्तारीकरण एवं गंगा नदी के किनारे बालू की बोरी का बैरियर लगाकर प्रवाह को धीमा कर स्नानार्थियों हेतु सुरक्षित घाट बनाये जाने के कार्य को देखा तथा आवश्यक दिशा-निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने संगम नोज पर प्रमुख स्नान पर्वों पर स्नानार्थियों के आने व जाने के मार्ग, साइनेज, कोहरे के समय विजिबिलटी, सीसीटीवी कैमरे व साउंड सिस्टम, घाटों पर खस बिछाये जाने का कार्य, साफ-सफाई के कार्यों का निरीक्षण किया।

तत्पश्चात मण्डलायुक्त ने संगम नोज मार्ग पर सेक्टर कार्यालय के सामने बनाये गये टॉयलेटों की क्रियाशीलता, साफ-सफाई, पानी की सप्लाई, जेट स्प्रे से सफाई के कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टॉयलेटों में पानी की सप्लाई न होने तथा साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था न पाये जाने पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा टॉयलेट की साफ-सफाई के लिए नियुक्त सभी कर्मियों को बुलाकर साफ-सफाई की अच्छी स्थिति न होने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि पानी की आपूर्ति आज नहीं होने से साफ-सफाई का कार्य ठीक से नहीं हो पाया है। पानी की सप्लाई आते ही सभी टॉयलेटों को क्लीन कर दिया जायेगा। तत्पश्चात मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारी व

मेलाधिकारी के साथ सभी सेक्टर-4, 5 एवं तत्पश्चात सेक्टर-2 के सभी टॉयलेटों का निरीक्षण कर उनकी साफ-सफाई एवं क्रियाशीलता को देखा। सेक्टर-4, 5 एवं 2 में टॉयलेट क्रियाशील पाये गये एवं पानी की सप्लाई भी थी, परंतु सफाई हेतु नामित वेण्डर के द्वारा टॉयलेट के क्लीनिंग हेतु फिनायल, हार्पिक, दुर्गंधमुक्त केमिकल (ओडोर फ्री) एवं अन्य आवश्यक सामान सफाई कर्मियों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था, जिसपर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बंधित वेण्डरों के दो प्रतिशत का अर्थदण्ड लगाये जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी टॉयलेटों की नियमित साफ-सफाई के साथ ओडोर फ्री बनाये रखने के निर्देश दिए है। मण्डलायुक्त ने सेक्टर-1, 2, 4 एवं 5 के सेक्टर मार्गों पर रखीं हुई कम्युनिटी डस्टबिनों एवं उनमें लगाये गये लाइनर बैग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों से कितने डस्टबिनों एवं लाइनर बैग की आवश्यकता है, कितनी उपलब्धता है, की जानकारी लेते हुए सभी मार्गों पर साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। निरीक्षण के दौरान सेक्टर-4 की सड़क पर कुछ स्थानों पर सामानों की बिखरे पॉलीथिन बैगों को डस्टबिन में रखने के निर्देश दिए और सफाई इंस्पेक्टर से कहा कि मार्गों पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं दिखनी चाहिए और डस्टबिनों को नियमित रूप से खाली किया जाये। उन्होंने सफाई इंस्पेक्टर से सैनिटेशन कालोनी में रहने वाले सफाई कर्मियों को उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल, खाने-पीने की व्यवस्था, शौचालय, अलाव की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी से सेक्टरों में एम्बुलेंस व चिकित्सकों की टीम लगाये जाने एवं मेला क्षेत्र का विजिट कर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने थाना खाकचौक एवं अग्निशमन केन्द्र का भी निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मण्डलायुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ माघ मेला-2026 में सुगम यातायात हेतु बनायी गई पार्किंगों का निरीक्षण कर वहां पर की गयी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 3 में बनायी गयी पार्किंग, बदरा सनौटी पार्किंग, झूंसी बस स्टैण्ड पार्किंग, छतनाग पार्किंग, सलोरी के सामने बनायी गयी पार्किंग का निरीक्षण किया तथा वहां पर पानी, बिजली, सीसीटीवी कैमरा, टॉयलेट आदि की व्यवस्था को देखा तथा उन्होंने सभी सम्बंधित अधिकारियों को सभी पार्किंग स्थलों में आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए है। तत्पश्चात फाफामऊ ब्रिज पर ट्रैफिक लोड को घटाए जाने एवं जाम आदि की समस्या के समाधान तथा लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर एवं उत्तर दिशा से आने वाले स्नानार्थियों और श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र पहुँचने में किसी प्रकार की समस्या ना हो इसलिये फाफामऊ ब्रिज के पास बनाये जा रहे दो पांटून पुलो एवं कनेक्टिंग मार्ग का निरीक्षण कर कार्य प्रगति का जायजा लिया तथा सम्बंधित अधिकारियो को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने फाफामऊ में बनाए गए घाट का भी निरीक्षण किया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

आप ने दिल्ली में यमुना के घाट पर करवाया हवन, लगाए सरकार पर गंभीर आरोप

(जीएनएस)।

आम आदमी पार्टी ने छठ महापर्व के दौरान भाजपा सरकार के किए गए पापों को माफ करने के लिए बुधवार को यमुना पर पर हवन किया। दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल समाज की तरफ से "आप" विधायक संजीव झा, पूर्व विधायक अखिलेश त्रिपाठी और विनय मिश्रा ने कालिंदी कुंज स्थित छठ घाट पर हवन कर छठी मैया से भाजपा सरकार की विफलताओं के लिए उसे माफ करने के लिए प्रार्थना की।

इस बाबत "आप" के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा की सरकार ने पाप किया है। दिल्ली के पूर्वांचली लोगों से झूठ बोलकर, सीवर के पानी से छठी मैया और सूर्या भगवान को अर्घ्य दिलवाने का पाप करवाया गया। "आप" द्वारा भाजपा सरकार के पापों को माफ करने के लिए मां यमुना पर यह हवन कराया गया।

हवन के उपरांत बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने कहा कि दो दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वीकार किया कि यमुना के पानी में जा नहीं सकते, आचमन करना तो दूर की बात है। यह यमुना का पानी नहीं, बल्कि खराब सीवर का पानी है। छठ पूजा पूर्वांचल वासियों की आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, जो साफ-सफाई का पर्व है। उस महापर्व पर भाजपा के नेताओं ने कहा था कि जाकर यमुना में आचमन कीजिए, पानी एकदम साफ है।

संजीव झा ने कहा कि आज हम भगवान सूर्य (भास्कर) से माफी मांगने आए थे और इसीलिए हमने यमुना किनारे हवन किया। भाजपा के लोगों ने गुमराह करके सीवर के पानी से आचमन करवाया, जिससे हमारी छठ पूजा अशुद्ध हो गई। हम सभी पूर्वांचल वासियों की ओर से भगवान भास्कर से माफी मांगते हैं कि भाजपा के गलत प्रोपेगेंडा के कारण पूजा अशुद्ध हुई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट को सद्बुद्धि दें, ताकि वे आस्था के महापर्व पर इस तरह का झूठ न बोलें और हमारे आस्था के महापर्व के साथ खिलवाड़ न करें।

संजीव झा ने कहा कि यमुना के हालात बहुत बुरे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अक्टूबर में भाजपा के सभी नेताओं ने यमुना किनारे आकर आचमन और स्नान किया था। उस समय उन्होंने दावा किया था कि यमुना साफ हो गई है और लोग इसमें स्नान व आचमन कर सकते हैं। आज दो महीने बाद वही पर्यावरण मंत्री सिरसा जी चेतावनी दे रहे हैं कि यमुना में नहाने मत जाना, अन्यथा गंभीर

बीमारियां हो सकती हैं। यमुना ने अब नाले का स्वरूप ले लिया है और यह भाजपा सरकार के पापों का परिणाम है। यमुना हर तरफ झाग दिख रहा है, जैसे बर्फ गिरी हो। मां यमुना भाजपा के लोगों को कभी माफ नहीं करेंगी।

संजीव झा ने एक्स पर कहा कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का हालिया बयान है कि यमुना का पानी डुबकी लगाने लायक नहीं, बल्कि सीवर का पानी है, यह स्वीकारोक्ति है कि यमुना की सच्चाई क्या है? जबकि कुछ महीने पहले तक दिल्ली सरकार दावा कर रही थी कि यमुना का पानी एकदम साफ है और आचमन करने योग्य है। इस दोहरी राजनीति ने छठ पूजा जैसी पवित्र आस्था का मजाक बना दिया। पूर्वांचल समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है और श्रद्धालुओं को गंदे पानी में आस्था निभाने के लिए भ्रम में रखा गया। इसी पीड़ा के साथ, एक पूर्वांचली होने के नाते, अपने साथियों पूर्व विधायक अखिलेश त्रिपाठी और विनय मिश्रा के साथ कालिंदी कुंज छठ घाट पर हवन कर भगवान भास्कर और छठी मैया से क्षमा प्रार्थना की कि सरकार की विफलता के कारण हमारी आस्था को ठेस पहुंची।

इस दौरान पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि तीन महीने पहले भाजपा सरकार ने आस्था को ठेस पहुंचाई। हिंदू धर्म के महापर्व और पूर्वांचलियों की आस्था के प्रतीक छठ पूजा, जो साफ-सफाई का पर्व है, उसमें लोगों को गंदे यमुना पानी में अर्घ्य देने और आचमन करने के लिए मजबूर किया गया। आज हम छठी मैया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने और हवन करने इकट्ठे हुए हैं कि हमें माफ करें, क्योंकि भाजपा और दिल्ली सरकार ने हमारे आस्था के इस महापर्व को दूषित करने का काम किया है।

अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि जिस तरह भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी सरकार की पोल खोली है, उससे लोगों को पता चल गया है कि भाजपाई किसी धर्म के नहीं हैं। इन्होंने हिंदू धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। भाजपा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद पानी पीकर लोगों को विश्वास दिलाया था कि पानी साफ है। इन्हीं के विधायक रवि नेगी ने भी झूठा दिखावा करते हुए बोतल में पानी भरकर पिया था और पूर्वांचल के लोगों से आचमन करने को कहा था। जिन लोगों ने भाजपा के लोगों की बातों पर विश्वास करके यमुना जी पर व्रत और आचमन किया, उन सबका व्रत दूषित और खंडित हो गया। भाजपा ने यह महापाप किया है, जिसका उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा और पूर्वांचल वासियों से माफी मांगनी चाहिए।

वहीं, पूर्व विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि यह बड़ा गंभीर और दुखद मुद्दा है। छठ हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। गांव में भी जब यह पूजा होती है, तो पहले पूरे घर को गौ माता के गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है क्योंकि इसमें साफ-सफाई बहुत जरूरी होती है। व्रती इसमें लगभग 72 घंटे का उपवास रखते हैं और विशेष ध्यान रखा जाता है कि आसपास सफाई रहे। लेकिन दो माह पहले भाजपा के गलत प्रोपेगेंडा के कारण दिल्ली में जिस तरह हमारी आस्था और पूजा के साथ खिलवाड़ हुआ, वह अत्यंत निंदनीय है।

विनय मिश्रा ने कहा कि छठ के समय मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक सहित भाजपा के सभी बड़े-बड़े नेताओं ने छठ घाटों और यमुना किनारे आकर दिल्ली वालों से झूठ बोला। उन्होंने पानी में हिलोरे लेकर दिखाया कि देखो हमने यमुना साफ कर दी है और लोग इसमें छठ पूजा कर सकते हैं। लेकिन दो दिन पहले भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुद टीवी पर आकर स्वीकार किया कि यमुना में मत नहाना और आचमन मत करना क्योंकि इसमें सीधा सीवर का पानी आ रहा है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री समेत भाजपा के मंत्रियों ने छठ के समय दिल्ली की जनता और पूर्वांचल के लोगों से झूठ बोला।

विनय मिश्रा ने कहा कि इसीलिए आज हम यहां क्षमा याचना पूजा और हवन करने आए थे। हमने सूर्य भगवान से माफी मांगी कि हे भगवान, भाजपा की वजह से हम लोगों से जो पाप हुआ है, उसके लिए हमें माफ करें। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे से भाजपा के बहकावे में न आएं। उन्होंने पूर्वांचलियों से भी अपील की कि वे अपने घरों पर सूर्य भगवान से क्षमा याचना करें कि भाजपा की वजह से जो दिक्कत हुई है, उसे माफ करें और भगवान भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि दें।